सस्ते आवासीय होटल खोलना

980. **श्री हुक्म देव नारायण यादव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सस्ते आवासीय होटल खोलने का है, और यदि हां, तो ऐसे होटल किन स्थानों पर खोले जायेंगे ,

(ख) क्या सरकार का विचार "फाइव स्टार" होटलों के निर्माण पर तथा उनके लिए बैंकों तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों से ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगाने का है, और

(ग) यदि हां तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) मैट्रोपॉलिटन शहरों (दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास) तथा अन्य चुने हुए पर्यटन केन्द्रों पर सस्ते होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय क्षेत्र में बनाये जाने वाले ऐसे होटलों की संख्या तथा स्थान छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिस पर योजना आयोग के साथ बातचीत की जा रही है, इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध किए गए साधनों पर निर्भर करेंगे ।

(ख) और (ग). भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को दृष्टि में रखते हुए पांच स्टार वर्ग के होटलों की भी आवश्यकता है । अत पांच स्टार वाले होटलों के निर्माण तथा बैंकों एवं अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से उनके लिए ऋणों की व्यवस्था पर फिलहाल कोई प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव नहीं है ।

बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं द्वारा किसानों और अन्य व्यक्तियों को ऋण दिया जाना

981. **श्री हुक्म देव नारायण यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में विकास खण्ड मुख्यालयों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखायें किसानों और अन्य लोगों को ऋण नहीं देती और उस प्रतिशत धनराशि रिश्वत के रूप में मांगते है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कार्यों की जांच करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं ने सितम्बर, 1977 के अन्त तक कृषि सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दरभंगा और मधुबनी जिलों में क्रमश. 105 65 लाख रुपये और 33. 40 लाख रुपये का ऋण दिया था । पात्र आवेदकों को ऋण त्वरित गति से दिया जाता है और कोई पारितोषिक नहीं मांगा जाता है ।

(ख) यदि कोई खास मामले सरकार के ध्यान में लाये गये तो उचित कार्रवाई की जायेगी ।

नोटों का विमुद्रीकरण

982. **श्री हुक्म देव नारायण यादव :**
डा० रामजी सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन का पता लगाने के लिए वांचू समिति की सिफारिश मान कर

सरकार नोटों का विमुद्रीकरण करना चाहती है; और

(ख) देश मे अनुमानतः कुल कितना काला धन है और क्या उसका पता लगाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है ।

(ख) सरकार ने देश मे मौजूद काले धन का कोई अनुमान नहीं लगाया है । तथापि वांचू समिति ने ऐसी आय को जिसके सम्बन्ध में 1968-69 में कर का अपवंचन किया गया था, 1400 करोड़ रुपया आंका था ।

काले धन का पता लगाने की कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है । सरकार के द्वारा समय-समय पर स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है । कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 के द्वारा काले धन का पता लगाने तथा उसके बढ़ाव को रोकने के कार्य में सुविधा देने के प्रयोजन से कानून में कई एक संशोधन किये गये । तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 मे तस्कर व्यापारियों तथा विदेशी मुद्रा का कपटपूर्ण धंधा करने वाले व्यक्तियों की गर-कानूनी तौर पर प्राप्त की गई सम्पत्तियो को जब्त कर लेने की व्यवस्था की गई है ।

आयकर विभाग की गुप्तचर्या प्रशासन को करों की चोरी से संबंधित जानकारी के लिए प्रभावपूर्ण कार्रवाई कर सकने के लिए सुव्यवस्थित कर दिया गया है । आयकर/धनकर के नये करदाताओं का पता लगाने के लिए तथा विद्यमान करदाताओं के मामले में उनकी छुपी आय अथवा उनके छुपे धन का पता लगाने के लए गहन किंतु सुव्यवस्थित सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।

Opening of new branches and advances made by public and private sector banks

983. SHRI K. SURYANARAYANA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of new branches opened since during the last three years upto the end of June, 1977 by public sector and private sector banks; and

(b) the advances made by them for various developmental activities in the country i.e., Agriculture, small industries and professionals and self employed persons etc. during the above period?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) The required information is given in *Annexure-I*. [Placed in Library. See No. LT 1121/77].

(b) Available bank groupwise data regarding advances to neglected sectors as on the last Fridays of June 1975, June 1976 and March 1977 are set out in *Annexure II*. (placed in Library. See. No. LT 1121/77).

Loan to India by West Germany

984. SHRI RAJ KESHAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether West Germany has agreed to extend loan to India;

(b) if so, the amount granted and released; and

(c) the projects on which the amount is likely to be utilised?